राज्य सरकार ने छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म के दो सेट दिए और सिलाई के लिए खातों में भेजे 200 रुपए

सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की चमक, आठवीं तक के **67 लाख स्कूली बच्चों को नि:शुल्क**

जयपुर. राज्य के सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को राज्य सरकार ने नि:शुल्क यूनिफॉर्म की सौगात दी है। करीब 67 लाख बच्चों को सरकार ने पिछले सत्र में यूनिफॉर्म के दो सेट वितरित किए। इसके अलावा यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके बाद 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया। वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय विद्यालयों में आठवीं तक के बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख से अधिक बच्चों और पंजीकृत मदरसों में शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति छात्र दो सेट यूनिफॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

अभिभावकों पर कम हुआ भार

सरकार की ओर से लागू की गई इस योजना से जहां बच्चों को यूनिफॉर्म मिली है, वहीं अभिभावकों की जेब पर भार कम हुआ है। बच्चों को जहां आठवीं तक सरकार नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है, वहीं अब उन्हें यूनिफॉर्म मिलने से अभिभावकों को खर्चा नहीं करना पड़ रहा।

यूनिफॉर्म का गणित

- 8 वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म
- 67 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित
- 2 सेट यूनिफॉर्म का नि:शुल्क वितरण
- 200 रुपए सिलाई के लिए

मॉडल स्कूलों में भी मिलेगा लाभ

सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण के बाद अब स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके लिए हर मॉडल स्कूल के विद्यार्थी को 740 रुपए यूनिफॉर्म और सिलाई के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए करीब 2.13 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राज्य में 134 स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल हैं। इनमें कक्षा 6 से 8 वीं तक 28781 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

'डायल फ्यूचर' से मिलेगी भविष्य की राह

जयपुर. प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है। विभाग 'डायल फ्यूचर' (भविष्य की राह) कार्यक्रम चला रहा है। सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों का संकाय चयन में मार्गदर्शन करने के साथ कॅरियर काउंसलिंग की जा रही है। दसवीं पास करने के बाद बच्चे विषय चुनाव को लेकर असमंजस में रहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक बच्चों को सही संकाय चयन के साथ दसवीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा की भी जानकारी देंगे, जिससे वे कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बन सकेंगे। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों के कॅरियर चयन की राह आसान होगी।

क्या है डायल फ्यूचर

डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टेप्स (भविष्य की राह) इनिशिएटिव के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक-एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक के रूप में चयन किया गया है, जो स्कूल में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का संकाय चयन में मार्गदर्शन एवं कॅरियर काउंसलिंग करेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश को 4 जोन जयपुर जोन (जयपुर एवं भरतपुर संभाग), कोटा जोन (कोटा एवं उदयपुर संभाग), जोधपुर जोन (जोधपुर एवं पाली संभाग) तथा बीकानेर जोन (बीकानेर, चूरू एवं अजमेर संभाग) में बांटकर 20 हेल्प डेस्क नंबर 9773319741 से 9773319760 तक जारी किए गए हैं।

9 लाख विद्यार्थियों की कॅरियर कांउसलिंग

दसवीं कक्षा के बाद चुने गए विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। विषय का चयन विद्यार्थी के भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण पड़ाव है। फायदा यह होगा कि संकाय चयन में मार्गदर्शन मिलने के साथ ही निकटतम विद्यालय की भी जानकारी मिलेगी। डायल फ्यूचर कार्यक्रम के माध्यम से इसी सत्र में करीब 9 लाख विद्यार्थियों के कॅरियर की राह को उज्ज्वल बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर की टीम के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है।

9401 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम बनेंगे राज्य में 12397 स्कूल स्मार्ट हो जाएंगे

स्कूलों में स्मार्ट होंगे क्लास रूम, डिजिटल शिक्षा मिलेगी

जयपुर. कोविड के बाद शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हो गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनाई जा रही हैं। राज्य में पहले से ही 2996 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम हैं। अब नए सत्र से 9401 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब 12397 स्कूल स्मार्ट हो जाएंगे। आईसीटी योजना के तहत 114 करोड़ रुपए इनके निर्माण में खर्च किए जाएंगे।

यह होगा फायदा

स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड, सेट टॉप बॉक्स, एंटिना सहित अन्य कई तरह की सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए विद्यार्थियों को समय समय पर ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकेगा। क्लास रूम में इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले लगाई जाएगी। इसके जरिए बच्चे ऑडियो, वीडियो और कहानियों आदि के माध्यम से पढ़ सकेंगे। कोरोनाकाल में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की काफी आवश्यकता महसूस की गई थी।

किस जिले में कितने स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम

- जयपुर : 632
- नागौर : 601
- अलवर : 524
- उदयपुर : 503
- भरतपुर : 461
- जोधपुर : 441
- भीलवाड़ा : 424
- अजमेर - 272
- टोंक : 289
- धौलपुर : 200
- करौली : 193
- सवाईमाधोपुर : 184
- बीकानेर : 221
- श्रीगंगानगर: 271
- हनुमानगढ़ : 194
- चूरू : 107
- झुंझुनूं : 134
- सीकर : 360
- दौसा : 296
- बाड़मेर : 381
- जैसलमेर : 119
- जालोर : 207
- पाली : 264
- सिरोही : 150
- बारां : 195
- बूंदी : 151
- झालावाड़ : 238
- कोटा : 213
- बांसवाड़ा : 228
- चित्तौड़गढ़ : 353
- डूंगरपुर : 275
- प्रतापगढ़ : 122

402 सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, बेहतर सुविधाओं और नामांकन बढ़ोतरी से रिकॉर्ड संख्या में चयन

स्मार्ट पाठशाला से संवर रहा भविष्य

जयपुर. राज्य के 402 सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों को टक्कर देते नजर आएंगे। ये स्कूल और स्मार्ट होंगे। इन स्कूलों ने केंद्रीय योजना में जगह बनाई है। नामांकन बढ़ोतरी, बेहतर सुविधाओं, पक्के भवन, अलग-अलग शौचालय, साफ-सुथरी कक्षा, लाइब्रेरी और खेल-मैदान जैसे मापदंड पूरे कर ये इस योजना में शामिल हुए हैं। इसमें पूरे देश से 14597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। यह पहला मौका है कि इस योजना में एक साथ राज्य के इतने स्कूलों का चयन हुआ है। अब इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। यहां प्राइमरी से सीनियर सैकंडरी तक की शिक्षण व्यवस्था होगी। स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केन्द्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे।

ये सुविधाएं होंगी

मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। स्कूलों के ढांचागत विकास के साथ स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लैब आदि कई तरह की सुविधाएं यहां होंगी।

इनमें प्राइमरी से सीनियर सैकंडरी तक की पढ़ाई हो सकेगी। इससे विद्यार्थियों को बार-बार स्कूल बदलने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। इन स्कूलों के प्रबंधन का यह काम भी होगा कि ये अपने आस-पास के स्कूलों के विकास का भी प्रयास करेंगे।

इन जिलों के इतने स्कूल शामिल

जयपुर	28	चितौड़गढ़	13	करौली	9
जोधपुर	24	जालोर	12	कोटा	9
उदयपुर	22	पाली	11	धौलपुर	8
बाड़मेर	21	बांसवाड़ा	11	राजसमंद	8
अलवर	19	दौसा	11	टोंक	8
नागौर	18	झालावाड़	10	चूरू	7
भीलवाड़ा	15	बीकानेर	10	जैसलमेर	7
सीकर	14	बारां	10	सवाई माधोपुर	7
अजमेर	14	डूंगरपुर	10	सिरोही	6
भरतपुर	14	प्रतापगढ़	9	बूंदी	5
श्रीगंगानगर	13	हनुमानगढ़	9		

मदरसों में भी बनाए जा रहे स्मार्ट क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड की जगह अब स्मार्ट बोर्ड

जयपुर। राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मदरसों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत की जा चुकी है। मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में 13.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम व इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से करवाए जाने की घोषणा की थी।

सरकार का बालिका सुरक्षा पर फोकस...स्कूलों में बालिकाओं को दिया जा रहा गुड टच और बैड टच का प्रशिक्षण

शिक्षा के साथ छात्राएं सीख रहीं आत्मरक्षा के गुर

जयपुर. प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के साथ ही कई अन्य पैरामीटर्स पर बालिकाएं निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बालिका शिक्षा सदैव से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकता में शामिल रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार बालिका शिक्षा के साथ-साथ बालिका सुरक्षा पर भी फोकस कर रही है। वहीं बालिकाएं अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों को उड़ान दें, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। बालिका सुरक्षा पर भी अब राज्य सरकार काम कर रही है। अगस्त से दिसंबर माह के बीच सभी स्कूलों में बालिकाओं को गुड टच और बैड टच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए टीचर्स का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा रहा है। इसके अलावा नए सत्र में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए छात्राओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बाद श्रेष्ठ बालिकाओं के बीच राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने की भी योजना है।

अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि

- गार्गी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाली 2.40 लाख बालिकाओं को 71.89 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
- बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में वर्तमान सरकार ने 1.86 लाख बालिकाओं को 93.15 करोड़ रुपए की राशि दी है
- मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अन्तर्गत 1514 बालिकाओं को 11.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है
- आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत 75757 बालिकाओं को15.72 करोड़ रुपए की राशि दी गई हैं
- शारीरिक रूप से अक्षम बालिकाओं के लिए आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना राज्य सरकार चला रही है। इस योजना के अन्तर्गत 5063 बालिकाओं को 1.36 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
- इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजनान्तर्गत 2255 बालिकाओं को 19.63 करोड़ रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

छात्रवृत्ति से मिल रहा प्रोत्साहन

जयपुर. राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए कई प्रकार की छात्रवृत्ति उन्हें दी जा रही है। ज्यादातर छात्रवृत्ति में फीस का पुनर्भरण सरकार कर रही है, ताकि फीस पढ़ाई में बाधा न बने। कॉलेज स्तर पर ही नहीं बल्कि स्कूली स्तर पर भी छात्रवृत्ति दी जा रही है।

छात्रवृत्ति की प्रमुख योजनाएं

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
- सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
- देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग
- डॉ अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- डॉ.अंबेडकर विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्धघुमंतू उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रसारित

आठवीं कक्षा तक के 69 लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों में नि:शुल्क दूध

शिक्षा के साथ सेहत का ख्याल

सप्ताह में छह दिन दूध वितरण

जयपुर. राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब तंदुरुस्त नजर आएंगे। राजस्थान सरकार शिक्षा के साथ बच्चों के शारीरिक विकास पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकारी स्कूलों में आठवीं तक के करीब 69.22 लाख से अधिक बच्चों को प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद निशुल्क दूध वितरण किया जा रहा है। इससे स्कूलों में आठवीं कक्षा तक बच्चों की उपस्थिति में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने गत बजट में स्कूलों में बाल गोपाल दूध योजना की घोषणा की थी। पहले बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध पाउडर का वितरण होता था। अब सप्ताह में 6 दिन दूध वितरित किया जा रहा है। पहले सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने नए सत्र 2023-24 से इस योजना को दो दिन की बजाय छह दिन के लिए लागू कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अक्टूबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया।

यह रहती दूध की मात्रा

- कक्षा एक से 5 वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम दूध पाउडर, 8 ग्राम चीनी, 150 मिलीमीटर पानी
- कक्षा 6 से 8 वीं तक के बच्चों को 20 ग्राम दूध पाउडर, 12 ग्राम चीनी, 200 मिमी पानी

मिड-डे मील में भी मिल रहा पौष्टिक आहार: राज्य के सरकारी स्कूलों में एक ओर जहां बच्चों को दूध वितरण किया जा रहा है। स्कूलों में मिड डे मिल के जरिए पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। बच्चों को यह आहार खास पसंद आ रहा है। सरकार की ओर से शिक्षा अधिकारियों को समय-समय पर मिड डे मिल की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह है योजना की खासियत

- 8 वीं तक के बच्चों को वितरित हो रहा दूध
- सप्ताह में 6 दिन वितरित होता है दूध
- 69 लाख से अधिक बच्चे स्कूलों में पी रहे दूध

शिक्षा विभाग में नई भर्तियों से बदलेगी स्कूलों की सूरत

नए सत्र में मिलेंगे 70 हजार नए शिक्षक

एक करोड़ होगा स्कूलों में नामांकन

जयपुर. राज्य के सरकारी स्कूलों की दशा बदलने जा रही है। एक ओर सरकारी स्कूलों में नामांकन एक करोड़ के पास पहुंचने जा रहा है। वहीं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। नए सत्र में स्कूलों में करीब 70 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। राज्य के 64888 स्कूलों में वर्तमान में 90.64 लाख बच्चों का नामांकन है। इस सत्र में 13.53 लाख बच्चों का नामांकन हुआ है। नए सत्र 2023-24 में यह नामांकन एक करोड़ के पास पहुंच जाएगा।

सर्वाधिक 48 हजार शिक्षक तृतीय श्रेणी के आएंगे: शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार सैकंड ग्रेड के 9760 पदों पर परीक्षा हो चुकी है। वहीं, व्याख्याता के छह हजार पदों पर सत्यापन जारी है। कम्प्यूटर अनुदेशक के करीब साढ़े छह हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है।

925 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शुरू होंगी बाल वाटिकाएं

राज्य के 925 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बाल वाटिकाएं शुरू की गई हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रक्रिया भी पूरी की गई है। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एनटीटी शिक्षकों को महिला बाल विकास विभाग से लगाया जाएगा।

वंचित वर्गों के लिए स्कूलों की भारी फीस की चिंता अब दूर

इंग्लिश मीडियम स्कूलों में साढ़े तीन लाख बच्चे ले रहे क्वालिटी एजुकेशन

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने न केवल शिक्षा व शिक्षण व्यवस्था को सुधारा है बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन स्कूलों ने वंचित वर्ग के लिए स्कूल की भारी फीस की चिंता खत्म की है और निम्न वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा एक से बारहवीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत 33 जिला मुख्यालयों से की गई। जिला मुख्यालय स्तर पर एक-एक स्कूल शुरू किए गए। लोगों ने भी इन स्कूलों के प्रति अपार उत्साह दिखाया। पहले ही वर्ष सीटों के मुकाबले अधिक आवेदन पत्र आए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत इनकी संख्या बढ़ाई। प्रदेश में अब तक 2989 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू हो चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी।

30 सीट पर आए 2600 आवेदन

- राज्य सरकार ने हाल ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू कीं। इसके प्रति अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का अच्छा रुझान सामने आया है। अभिभावकों ने इन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में विशेष उत्साह दिखाया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तो 30 सीटों पर प्रवेश के लिए 2600 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश में वर्तमान में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अध्ययनरत हैं। राज्य के 1029 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने के साथ ही राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू की गईं। ऐसा करने वाला राजस्थान उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है।

200 से अधिक विद्यार्थी तो खुलेगी अलग विंग

- मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में घोषणा की है कि जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी सरकार प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ करेगी। प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर हों, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित करने की दिशा में शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है।

शिक्षकों का अलग काडर बनाया

इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने इसके शिक्षकों का भी अलग काडर बनाया है। बजट घोषणा के अनुरूप 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया चल रही है।

स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा का 'पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम' अब ऑनलाइन

जयपुर. प्रदेश में इस बार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाले पीसीपी (पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम) को ऑनलाइन मोड पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल से परीक्षार्थी प्रोग्राम अवधि की समाप्ति के बाद भी अपने से सम्बंधित कंटेंट का ऑनलाइन रिवीजन करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए पीसीपी प्रोग्राम के कंटेंट को डिजिटाइज किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय तथा ओपन स्कूल के तहत ऐसे कई नवाचारों को लागू किया जा रहा है। आरईआई पार्टनर्स एमओयू के तहत क्षेत्र या जिला विशेष के लिए अपनी प्रोजेक्ट गतिविधियों के संचालन के साथ ही ऐसे इनोवेशन और अपने आईडिया साझा करने होंगे, जिससे सरकार और संस्थाओं की साझेदारी में विद्यार्थियों और लक्षित वर्ग को और बेहतर तरीके से लाभान्वित करने के मूल उद्देश्य को साकार किया जा सके।

आईसीटी लैब्स की क्रियाशीलता बढ़ेगी

विभाग के अधिकारी सभी प्रकार के ई-कन्टेंट का विश्लेषण सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए आईसीटी लैब को और अधिक क्रियाशील किया जाना जरूरी है। ऐसे में विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके पास आईटी से संबंधित डिग्री हो, जिससे उनके अनुभवों का उपयोग आईसीटी लैब संचालन के कार्यों में भी किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी ई-कन्टेंट से जोड़ने के निर्देश दिए।

स्कूलों में होगा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत, निर्माण कार्यों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग

जयपुर. राज्य सरकार का फोकस प्रदेश में शिक्षा के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। समग्र शिक्षा अभियान के वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में प्राइमरी सेटअप में 78 विद्यालयों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडेशन, आठवीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 96 प्राथमिक स्कूलों एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवनों की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सैकेण्डरी सेटअप के स्कूलों में 176 कम्प्यूटर रूम, 179 लाइब्रेरी रूम, 369 साइंस लैब, 100 आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, 290 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सैकेण्डरी विद्यालयों के 8 और सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के 20 नए भवन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 13 डाइट भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत, 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के नए भवन एवं 16 केजीबीवी के अपग्रेडेशन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार 'स्टार्स प्रोजेक्ट' में 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों के अपग्रेडेशन के कार्य कराए जाएंगे।

साथ ही, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उनकी 'डिजिटल मॉनिटरिंग' का 'मैकेनिज्म' तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्क्स की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां और वर्क ऑर्डर जारी करने की 'रियल टाइम बेसिस' पर मॉनिटरिंग होगी। वहीं फील्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति एवं उनके पूर्ण होने पर भुगतान जैसी स्टेज के बारे में त्वरित फीडबैक मिलेगा, इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

वर्ष 2015 में 70 स्कूलों से हुई थी शुरुआत, मौजूदा सरकार ने 2 हजार स्कूलों तक पहुंचाया यह कार्यक्रम

स्कूलों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, जिलों की परिस्थितियों के अनुसार कोर्स

जयपुर. प्रदेश में स्कूली बच्चों को भी व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2015 में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शुरुआत 70 राजकीय विद्यालयों में की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत सरकार की इस योजना को जारी रखते हुए आगे बढ़ाया। वर्ष 2022-23 में अब लगभग 2,000 विद्यालयों तक यह कार्यक्रम पहुंच चुका है। इन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को विभिन्न व्यवसाय एवं रोल्स का प्रशिक्षण देने के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं।

शिक्षा विभाग ने इस सत्र के दौरान प्रदेश में गत वर्ष जिन जिलों के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित है, उनमें रेंडम आधार पर कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों के कौशल की जांच के लिए 'पार्टी एसेसमेंट' कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए इस विभाग में ही रिसोर्स पर्सन तैयार किए जाएंगे, जो फील्ड में आकर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का आकलन करेंगे। इससे प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को नई दिशा देने में मदद मिलेगी। साथ ही फील्ड में इस संबंध में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का भी मार्ग प्रशस्त होगा। व्यावसायिक शिक्षा में राज्य के जिलों की परिस्थितियों तथा इंडस्ट्रीज की मांग के अनुसार नए कोर्स भी प्रारंभ करते हुए नये सत्र में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस फील्ड में अच्छा अनुभव रखने वाले 'ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ कार्य किया जाएगा।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं साधारण परिवारों के बच्चे

बदलते राजस्थान की तस्वीर, स्कूली शिक्षा में प्रदेश का शानदार प्रदर्शन

जयपुर. स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान नित नए पायदान हासिल कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में राजस्थान ने स्कूली शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के प्रदर्शन पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 25 जिलों ने अति उत्तम श्रेणी में जगह बनाई है। बच्चों में सीखने की क्षमता में राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह सूचकांक जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। इस प्रणाली में करीब 15 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के करीब साढ़े छह करोड़ छात्र शामिल हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में वर्तमान में 3.50 लाख विद्यार्थियों का तो नामांकन हो चुका था, यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। 1033 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (बाल वाटिकाओं) का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और खोले जाएंगे।

छोटे से गांव का सरकारी स्कूल: कनक, मनमीत, मनीषा व आयशा की धाराप्रवाह अंग्रेजी

महानगरों की अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर अजमेर के बोराज जैसे छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करते कनक, मनमीत, मनीषा व आयशा जैसे बच्चे राजस्थान के बदलते शैक्षणिक परिदृश्य की सुनहरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। यह संभव हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभिनव सोच से लागू हुई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के जरिए। इस योजना से न सिर्फ राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, बल्कि उन सभी माता-पिता के मन में पल रहे सपनों को नया आसमान भी मिला है, जो कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलवा पाने में अक्षम थे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रसारित

चीफ नेशनल कमिश्नर अवार्ड एंड फ्लैग अपने नाम कर राजस्थान बना सिरमौर, 52 राज्यों में राजस्थान रहा अव्वल, बनाए कई रिकॉर्ड

राष्ट्रीय जम्बूरी से कायम की मिसाल, राजस्थान में 67 साल बाद आयोजन

जयपुर. शौर्य एवं पराक्रम की धरा राजस्थान को 67 साल बाद भारत स्काउट एवं गाइड संगठन की राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ। देश के विभिन्न प्रांतों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की कला एवं संस्कृति के वाहक के रूप में लगभग 34 हजार 500 से अधिक स्काउट, गाइड, रोबर्स और रेंजर्स, के साथ-साथ बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाना, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, केन्या आदि देशों के 400 स्काउट इस सात दिवसीय बृहद आयोजन के साक्षी बने। राजस्थान के पाली जिले के निम्बली गांव एवं इससे लगती करीब 2 हजार बीघा जमीन पर 6 माह तक प्रशासन और भारत स्काउट एवं गाइड संगठन के अथक प्रयासों से एक अस्थामी गांव विकसित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी को जम्बूरी का उद्घाटन किया। इन 35 हजार स्काउट-गाइड के रहने के लिए 220 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.520 टेंट बनाए गए। राजस्थान की धरा पर आयोजित यह दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले वर्ष 1956 में प्रदेश में पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई थी।

52 राज्यों में अव्वल रहा राजस्थान

आयोजन में सम्मिलित हुए 52 राज्यों में राजस्थान अव्वल रहा। राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए 'नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग' और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए 'नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड' दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान ने अपने नाम किए। इस पूरे आयोजन के दौरान राजस्थान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

70 साल से किया जा रहा आयोजन

राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 70 साल से किया जा रहा है। वर्ष 1953 में पहली बार हैदराबाद में जम्बूरी का आयोजन किया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस आयोजन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। जम्बूरी का उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को एकजुट करना और राज्यों की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू करवाना है। भारत स्काउट-गाइड ने अपने संगठन के अंतर्गत देश में 52 राज्य बना रखे हैं। इनमें देश के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश भी शामिल हैं। भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स संगठन में 63 लाख से अधिक स्काउटस एवं गाइडस हैं। प्रदेश में 12 लाख से अधिक स्काउट्स एण्ड गाइड्स हैं। कोविड प्रबंधन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय जम्बूरी में शामिल हुए मेहमानों ने इस ऐतिहासिक आयोजन को राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

सिलेंडर से गैस लीक हुई तो रेग्यूलेटर ऑफ होगा, हार्ट अटैक आने से पहले पता चलेगा

सरकारी स्कूलों के बाल वैज्ञानिकों के नवाचारों की धाक

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना: राज्य के 37 बाल वैज्ञानिक नेशनल लेवल पर चयनित

टॉप 10 में चार सरकारी स्कूल के छात्र, जयपुर से कुल छह

जयपुर. स्कूली स्तर पर होने वाले नवाचारों में निजी के साथ सरकारी स्कूलों के बाल वैज्ञानिक भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। हाल ही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राज्य से 37 स्कूलों के बाल वैज्ञानिकों के नवाचारों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। खास बात है कि इनमें टॉप 10 में से चार बाल वैज्ञानिक सरकारी स्कूल से हैं। वहीं, कुल छह स्कूल जयपुर से हैं। जयपुर के बाल वैज्ञानिकों की ओर से प्रद र्शित किए नवाचार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे सिलेंडर से गैस लीक होने पर रेग्यूलेटर ऑफ होगा तो वहीं हार्ट अटैक आने से पहले व्य क्ति को पता चल जाएगा। पिछले दिनों चित्तौडगढ़ में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में 411 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ था, जिसमें से 388 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

लीक हुई तो सेंसर पकड़ लेगा

मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी स्कूल के 12 वीं कक्षा के बाल वैज्ञानिक मोहित साहू ने हादसे को रोकने के लिए गैस सिलेंडर लीकेज सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। अगर सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ तो अलार्म बजेगा। इसके लिए सिलेंडर के पास सेंसर लगाए हैं, जो गैस के रिसाव होते ही बजेंगे। इसके अलावा वातावरण में गैस के रिसाव का लेवल भी बताएंगे।

मोबाइल पर ईसीजी मॉनिटर

मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल के छात्र और वैशाली नगर निवासी रुशिल सारस्वत ने डिटेक्टर यंत्र बनाया है। इसे कोई भी व्य क्ति पहन सकता है। इस डिवाइस का नाम मोबाइल ईसीजी मॉनिटर है। इससे व्यक्ति की ईसीजी उसके मोबाइल पर एक ऐप के माध्यम से मॉनीटर की जा सकती है। व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई समस्या वह यूजर को अलर्ट भेज देता है। इससे हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

बनाया वायरलैस नोटिस बोर्ड

राजापार्क की रहने वाली और निजी स्कूल की छात्रा हर्षिता जेठवानी ने वायरलैस नोटिस बोर्ड बनाया है। अगर नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना लिखनी है तो उसे बार-बार लिखने की जरुरत नहीं। मोबाइल पर टाइम कर या बोलकर नोटिस बोर्ड पर लिखा जा सकता है।

बैंच में बनाया अपार्टमेंट: मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी स्कूल के छात्र अनंत जैन ने स्कूल बैंच बनाई है। अक्सर स्कूल बैग बैंच से पास जमीन रखते हैं। लेकिन इस बैंच में एक अपार्टमेंट बनाया है। इसमें स्कूल बैग, टिफिन सहित अन्य सामान आसानी से रख सकते हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

गुड्डी के सपनों को मिल रही ऊंची उड़ान

जयपुर. नागौर जिले के रूण गांव की बालिका गुड्डी चौहान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना (केजीबीवी) में पढ़कर सफलता के आसमां में ऊंची उड़ान भर रही है। एक साधारण किसान परिवार में पांच भाई-बहिनों में लाडली गुड्डी कमजोर आर्थिक स्थिति पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही थी मगर इसी बीच कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उसके जीवन में बदलाव की सौगात लेकर आया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, रूण (मूण्डवा) में प्रवेश मिलने के बाद गुड्डी स्कूल की सुविधाओं के बीच कई तरह के नवाचारों और अन्य गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग ले रही है।

हाल ही में गुड्डी का नॉमिनेशन राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। गुड्डी ने अपने प्रोजेक्ट में छोटे साइज के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार करने का आइडिया सुझाया है, जो कोविड जैसी महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के हालात में बड़ा उपयोगी माना गया। गौरतलब है कि केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा के साथ ही नि:शुल्क आवासीय सुविधा भी दी जाती है। राजस्थान में वर्तमान में 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 41 हजार से अधिक बालिकाएं नामांकित है। केजीबीवी में सभी बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा, भोजन एवं सुरक्षित आवास के अलावा पुस्तकें, शिक्षण सामग्री भी मुहैया कराई जाती है। साथ ही बालिकाओं को प्रतिमाह 150 रुपये की स्टाइपेंड राशि भी दी जाती है।

'यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के...'

पांच अलग-अलग विश्व कीर्तिमान बनाए, पढ़ाई से लेकर एक्टिविटी तक शामिल

दुनिया में राजस्थान की शिक्षा का परचम

जयपुर. प्रदेश की शिक्षा देश में ही नहीं, विश्व में भी चमकी है। शिक्षा विभाग ने पांच अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से कोरोनाकाल में जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स तैयार कर इसके माध्यम से पढ़ाई कराई गई। लर्निंग गैप्स की पूर्ति के लिए 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम' के तहत विद्यार्थियों को कंपिटेंसी बेस्ड वर्कबुक से शिक्षण द्वारा कक्षास्तर तक लाने की पहल की गई। इसके बाद राज्य स्तरीय कॉमन पेपर से मूल्यांकन कर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया गया। इसमें राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के 65 हजार विद्यालयों के लगभग 45 लाख विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल्स की जांच के लिए 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 'आर्टिफि शियल इंटेलिजेंस' (एआई) के माध्यम से किया गया। एआई के प्रयोग से इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का त्वरित मूल्यांकन कर स्कूल शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान बनाया।

ये कीर्तिमान बनाए

- गत साल गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राज्य के एक करोड़ 47 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- 'नो-बैग-डे' के नवाचार के तहत हमने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवम्बर 2022) से राज्य के स्कूलों में 'चेस इन स्कूल एक्टिविटी' का आगाज किया। इस दिन राज्य में एक साथ 38 लाख 21 हजार 9 विद्यार्थियों ने 'चेस इन स्कूल एक्टिविटी' में भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया।
- इस साल की शुरूआत में राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी को रोहट (पाली) में किया गया। इसमें देशभर व सार्क राष्ट्रों से लगभग 35 हजार स्काउट्स व गाइड्स ने भाग लिया। राज्य में 67 वर्ष बाद जम्बूरी के इस आयोजन में 'टेम्प्रेरी स्टेडियम निर्माण' का विश्व रिकार्ड स्थापित किया।

पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केन्द्रों एवं शहरों में वार्डों तक स्थापित

महात्मा गांधी पुस्तकालय जन-जन तक पहुंचा रहे राष्ट्रपिता का संदेश

जयपुर. राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने एवं प्रदेशवासियों में पढ़ने की रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय शुरू किए हैं। खास बात यह है कि ये पुस्तकालय एवं वाचनालय पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केन्द्रों एवं शहरों में वार्डों में स्थापित किए गए हैं। इन महात्मा गांधी पुस्तकालयों और संविधान केन्द्रों में पाठ्य पुस्तकें और समाचार पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लाइब्रेरी के लिए राज्य सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान भी किया है। ताकि पाठकों को पढ़ने के लिए पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध मिले। वे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को भी पढ़ और समझ पाएं।

इन केंद्रों में पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से 8869 महात्मा गांधी पुस्तकालय शुरू किए गए हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 14970 की जानी है। 11341 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों के संचालन के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अब हर शनिवार, रचनात्मक गतिविधियों का संसार

जयपुर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब हर शनिवार को रचनात्मक गतिविधियां आयोजित होंगी। प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चे रेडियो जॉकी बनेंगे तो वैज्ञानिक बनकर आविष्कार भी करेंगे। इसकी रूपरेखा शिक्षा विभाग ने बना ली है। इसके तहत अलग-अलग कक्षाओं की अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कक्षाओं के समूह बनाए जाएंगे। इनके नाम भी दिए गए हैं।

बच्चों के लिए कुछ खास

- हर माह के पहले शनिवार को विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित गतिविधियों का आयोजन होगा
- हर महीने के द्वितीय शनिवार को स्कूलों में नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपभोक्ता जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
- हर महीने की तीसरे और चौथे शनिवार को कक्षा तीन तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण भारत गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- जुलाई और अक्टूबर और जनवरी महीने के तीसरे शनिवार को विद्यार्थियों गुड टच व बैड टच संबंधित डॉक्यूमेंट्री और शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- जुलाई, सितंबर और जनवरी माह के पहले शनिवार को सड़क सुरक्षा में संबंधित गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी।

यह गतिविधियां की जा रहीं आयोजित

- **राजस्थान को पहचानो:** इसमें छात्र पशु-पक्षियों की विशेषताओं, व्यवसाय, जिलों की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, गांव के संसाधनों और नक्शे की जानकारी लेंगे
- **भाषा कौशल विकास:** इसमें छात्र सोचने, बोलने के कौशल का विकास करेंगे। इसके अलावा शब्द भंडार और भाषा का विकास, सुनने, समझने और प्रस्तुत करने, लेखन वाचन में मदद मिलेगी।
- **खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान:** इसमें बच्चे लंगड़ी टांग, कुर्सी दौड़, सांकल डंडा, लंबी कूद आदि खेल खेलेंगे। इससे बच्चों की शारीरिक क्षमता का विकास व एकाग्रता बढ़ेगी। बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होगा।
- **मैं वैज्ञानिक बनूंगा:** इसके तहत हमारी इंद्रिया, गरम, ठंडा पानी के साथ प्रयोग, बारिश मापने का यंत्र, गुब्बारा गाड़ी बनाना, कम्पोस्ट खाद बनाने जैसी गतिविधियां।
- **बालसभा अपनों के साथ:** इसके तहत बच्चे सफाई की बात अपनों के साथ, मेरी प्रतिभा तुम भी देखो, सामुदायिक बालसभा, गीत व कहानी प्रतियोगिता, विचार-विमर्श आदि गतिविधियां होंगी।

कई जिलों में स्कूल भवन निर्माण में नवाचार, दूसरे राज्य अपना रहे यह मॉडल

राज्य के स्कूली मॉडल की देश में चर्चा

बस-ट्रेन-प्लेन-जहाज में पढ़ रहे बच्चे

जयपुर. राजस्थान के सरकारी स्कूलों के भवनों में भी नवाचार किए जा रहे हैं। भवनों को इस तरह से बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे स्कूल आना पसंद करें। यही कारण है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। बच्चे स्कूल में खेल-खेल के साथ पढ़ भी रहे हैं। राजस्थान में सफलता के बाद अब दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। स्कूल शिक्षा के अभियंताओं को दूसरे राज्य भी बुला रहे हैं।

जनसहभागिता से हुआ संभव

भामाशाह स्कूल भवनों के निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में जनसहभागिता के तहत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। ये भवन स्टूडेंट्स फ्रेंड्ली हैं। स्कूलों में इस तरह के नवाचारों की देशभर में चर्चा है। दूसरे राज्यों के शिक्षा अधिकारी और अभियंता राजस्थान आकर इन भवनों का अध्ययन कर रहे हैं।

जानिए कहां किस तरह का मॉडल

प्रदेश के अलवर जिले के स्कूल भवनों पर सर्वाधिक नवाचार देखने को मिले हैं। इसके अलावा जयपुर, पाली, बीकानेर के स्कूल भी राज्य में पहचान बनाए हुए हैं। अलवर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारेड़ा में बस के आकार के भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। वहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहोड़ी का भवन अपने आप में आकर्षित करना है, जो निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हल्दिना अलवर का स्कूल पानी के जहाज के भवन में संचालित किया जा रहा है। इसीप्रकार कालीखोर का स्कूल ट्रेननुमा भवन में चल रहा है। बीकानेर में राजकीय महारानी स्कूल की कक्षाओं को इस तरह कलर किया गया है मानो ट्रेन के डिब्बे हों। पाली पंचायत समिति के गिरादड़ा गांव में बच्चों की कक्षा को हवाईजहाजनुमा बनाया गया है।

'आरटीई' से सम्बंधित शिकायतें कर सकेंगे व्हाट्सएप से

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हैल्पलाइन नम्बर के साथ ही 'वॉटसएप' नम्बर जारी

जयपुर. प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब 'वॉटसएप' के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हैल्पलाइन नम्बर के साथ ही 'वॉटसएप' नम्बर जारी किए गए हैं। प्रदेश में 'आरटीई' के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गत 19 मई को लॉटरी निकाली थी। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद विद्यालयों का चयन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर 2023 तक किया जा रहा है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर जारी 'वॉटसएप' नम्बर 7014812375 एवं 7014878012 पर शिकायत के सम्बंध में अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। 'वॉटसएप' पर शिकायत मिलने के बाद परिषद के स्तर पर अधिकरियों की एक समिति द्वारा नियमानुसार जांच कर इनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। इन 'वॉटसएप' नम्बर के अलावा हैल्पलाइन नम्बर 0141-2719073 एवं 0151-222140 पर किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नवाचार: सरकारी स्कूलों में शुरू होगी माइक्रो लर्निंग सिस्टम से पढ़ाई

शिक्षक बनाएंगे इनोवेटिव वीडियो

जयपुर. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है। इसके तहत कक्षा एक से आठवीं तक के 67 लाख बच्चों को किताबों के साथ-साथ अब खेल-खेल में वीडियो के माध्यम से टॉपिक समझाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग यह नवाचार कर रहा है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से माइक्रो लर्निंग सिस्टम से पढ़ाई कराने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में शिक्षक अब किसी भी कठिन टॉपिक को आसानी से समझाने के लिए इनोवेटिव वीडियो बनाएगा।

वीडियो को दिखाकर बच्चों को समझाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल के शिक्षक के इनोवेटिव वीडियो को जिला स्तर पर भेजा जाएगा। यहां से मूल्यांकन के बाद पूरे जिले के पांच टॉप वीडियो का चयन किया जाएगा। इन वीडियो को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास भेजा जाएगा। सभी जिलों से आने वाले श्रेष्ठ इनोवेटिव वीडियो को दीक्षा, शिक्षक सहित कई प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यहां से सभी शिक्षक उन वीडियोज को देख सकेंगे और अपने स्कूल में लागू करेंगे। इस नवाचार को लागू करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रशिक्षण करवाया जा रहा है।

अच्छा वीडियो बनाने पर पुरस्कृत होंगे बच्चे

जिला स्तर पर अच्छा वीडियो बनाने वाले पांच शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ राज्य स्तर पर चयनित टॉप 15 वीडियो बनाने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से टॉप 15 वीडियो एनसीईआरटी भेजे जाएंगे। यहां पर अलग-अलग राज्यों से आए इनोवेटिव वीडियो का मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही श्रेष्ठ वीडियो बनाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

कक्षा 3 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के आकलन के लिए अलग-अलग चरण में हुई परीक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से हुई 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

जयपुर. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम (आरकेएसएमबीके) के तहत शिक्षा विभाग ने बड़ा नवाचार किया है। इसके तहत कक्षा 3 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के आंकलन के लिए अलग-अलग चरण में परीक्षा आयोजित की गई। खास बात यह है कि इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षकों ने नहीं जांची। बच्चों ने ऑनलाइन एप के जरिए डिजिटल ओएमआर शीट की तरह ओसीआर शीट पर ही उत्तर लिखे, इसमें मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन अपलोड किए गए। शिक्षकों ने सिर्फ उत्तर पुस्तिका एप पर अपलोड की। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सॉफ्टवेयर के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान हुए लर्निंग गेप की भरपाई के लिए इस साल जुलाई में 'शिक्षा के बढ़ते कदम' अभियान के माध्यम से नवाचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को दक्षता आधारित शिक्षण से अपग्रेड किया जा रहा है। ये अभियान रेमेडिएशन पर केंद्रित है। अभियान की खास बात ये है कि इस अभियान में शिक्षकों का भी ध्यान रखा गया है। उनका कार्यभार कम किया गया है, ताकि वे ज्यादा समय तक पढ़ाई और अध्यापन में दे सकें।

यह है अभियान में

विद्यार्थियों को अपडेट करने के लिए दक्षता आधारित वर्क बुक्स तैयार की गई। कक्षा एक की वर्क बुक को प्रथम नाम दिया गया और इसमें ग्रेड लेवल वन के तहत कार्य करवाया जा गया। कक्षा दो की वर्क बुक को पल्लव नाम देते हुए लेवल टू के तहत कार्य, कक्षा तीन को पहल के तहत बिहाइंड ग्रेड लेवल वन और टू के तहत कार्य, कक्षा 4 और 5 को प्रयास वर्क बुक के तहत बिहाइंड ग्रेड लेवल 2, 3, 4 तय किया गया। कक्षा 6, 7 के लिए प्रवाह में बिहाइंड ग्रेड लेवल 3, 4, 5 तय किया गया। कक्षा 8 के लिए छठा चरण प्रखर जिसमें बिहाइंड ग्रेड लेवल 5, 6, 7 तय किया गया।

छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी

12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने पर छात्राओं को मिल रही स्कूटी

जयपुर. स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद भी छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार उन्हें स्कूटी बतौर प्रोत्साहन दे रही है। विभिन्न वर्गों की छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बारहवीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार स्कूटी दे रही है।

1. कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना : डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही कई स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित तौर पर

अध्ययन करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। स्कूटी के लिए इन वर्गों की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत 16,123 स्कूटी वितरित की गई है।

2. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना : अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को इस योजनान्तर्गत स्कूटी दी जा रही है। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजस्थान मूल की अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो। अभी तक इस योजना के लिए 3,937 स्कूटी वितरित की गई है।

इस वर्ष बढ़ाई जा रही स्कूटियों की संख्या

कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि वर्ष 2023-24 में स्कूटियों की संख्या 20000 से बढ़ाकर 30000 करने की घोषणा बजट में की गई है। साथ ही छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी दिया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की 17537 एवं वर्ष 2023-24 की 26,305 स्कूटी वितरित की जाएंगी। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की 2,463 एवं वर्ष 2023-24 की 3,695 स्कूटी वितरित की जाएंगी।